www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY/169/2015-2017

प्रखर...मुखर...स्वर

विदर्भ की बात
SUNDAY

● वर्ष 17 ● अंक 216 | नागपुर, रविवार, 2 जुलाई 2017 | ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

यूपी में अनेक किसानों के फसली ऋण माफी के दायरे में नहीं

लखनऊ

किसानों के स्वयं सहायता समूहों और संयुक्त दायित्व समूहों द्वारा प्राप्त किये गए फसली ऋण राज्य सरकार की फसली ऋण माफी योजना के तहत माफ नहीं किये जाएंगे। फसली ऋण माफी योजना के बारे में जारी शासनादेश में सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है। शासनादेश में कहा गया है कि यदि किसी किसान ने खेती की एक ही जमीन पर एक ही उद्देश्य के लिए एक से अधिक बैंकों से कर्ज लिया है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि किसान ने विभिन्न फसलों के लिए एक से अधिक बैंकों से विभिन्न कृषि भूमियों को बंधक रखे जाने के एवज में कर्ज लिया है तो उसे ऋण माफी का लाभ एक लाख रुपये की सीमा तक आनुपातिक रूप में ही मंजूर किया जाएगा।

मछली पालन का कर्ज भी माफ नहीं

फसली ऋण को छोड़कर मछली पालन या कृषि से जुड़े किसी प्रकार के क्रियाकलाप के लिए यदि कर्ज लिया गया है तो वह भी इस योजना के दायरे से बाहर होगा। ऐसे मामले, जहां किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े खाते से निकाली गई धनराशि का दुरुपयोग किया गया हो या उसको खेती के लिए इस्तेमाल न कर अन्य किसी आवधिक या आवर्ती जमा खाते में जमा किया गया हो, वे भी फसली ऋण माफी योजना से कवर नहीं होंगे। किसानों को कंपनियों या अन्य कार्पोरेट संस्थाओं द्वारा प्रत्याभूत ऋण भले ही ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा वितरित किया गया हो तथा न्यास, साझीदारी, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं/अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा दिया गया ऋण भी माफ नहीं होगा।

राजस्थान: बछड़े को बचाने के दौरान जहरीली गैस से तीन की मौत

जयपुर

राजस्थान के बारान जिले में जहरीली गैस के कारण तीन लोगों की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गहरे गड्ढे में गाय का एक बछड़ा गिर गया था जिसे बचाने के लिए तीन लोग उस गड्ढे में उतर गए। पुलिस के मुताबिक शाम मंगरोल में रामेश्वर (26), जितेंद्र (18), ओमप्रकाश (50) गहरे गड्ढे में उतर कर गाय के बछड़े को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों गड्ढे के अंदर जाते ही जहरीली गैस की चपेट में आ गए जिसके चलते वे बेहोश हो गए। उन तीनों को किसी तरह बाहर निकाला गया। बेहोशी की हालत में उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

आइसीएआइ समारोह में पीएम मोदी बोले

सीए के सिग्नेचर में पीएम की साइन से ज्यादा ताकत होती है

सरकार ने 37 हजार फर्जी कंपनियों की पहचान की

जीएसटी लागू होने से 48 घंटे पहले एक लाख कंपनियों पर लगा ताला

नई दिल्ली

देश भर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक जुलाई से लागू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के चार्टर्ड अकाउंटेंटों को संबोधित किया। आइसीएआइ के स्थापना दिवस पर इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में पीएम ने देश के आर्थिक विकास में सीए के योगदान का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आगे बढ़ाना है तो सीए को अपना काम ईमानदारी से करना होगा। पीएम ने कहा कि नोटबंदी के बाद सरकार ने हजारों की संख्या में फर्जी कंपनियों की पहचान की है और जीएसटी लागू होने से 48 घंटे पहले एक लाख कंपनियों पर ताला लगा है। आपके सिग्नेचर पर सवा सौ करोड़ भारतीयों का भरोसा है, उस भरोसे को टूटने मत दीजिए। आपका भरोसा कभी टूटा है तो आप ईमानदारी के उत्सव में शरीक हो जाइए। पीएम के सिग्नेचर की ताकत उतनी नहीं होती जितनी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की होती है। हर साल करोड़ों गाड़ियां खरीदी जाती हैं, लेकिन टैक्स नहीं दिया जाता। सरकार ने 37 हजार फर्जी कंपनियों की पहचान कर ली गयी है।

जीएसटी लागू होने से 48 घंटे पहले एक लाख कंपनियों पर ताला लगा है। 11 साल में सिर्फ 25 चार्टर्ड अकाउंटेंटों पर कार्रवाई हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या देश में 32 लाख लोग ही 10 लाख से ज्यादा कमाई करते हैं। मुझे बताया गया है कि इस देश में दो लाख 72 हजार से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। दोस्तों-मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये फर्जी कंपनियां किसी न किसी के पास तो जरूर गई होंगी। जिन्होंने ऐसे लोगों को सहारा दिया हो, जिन्होंने ऐसे लोगों को रास्ता दिखाया हो। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत लगती है कि नहीं। ऐसे लोगों को किनारे लगाने का समय आ गया है। फर्जी कंपनियों को खत्म करने से किसी राजनीतिक दल को कितना नुकसान हो सकता है, उसका मुझे पता है, लेकिन किसी न किसी को देश के लिए जीना पड़ेगा।

■ शेष पृष्ठ 2 पर

लागू किया गया जीएसटी वास्तविक मसौदे से अलग - चिदंबरम

नई दिल्ली

स्वतंत्रता के बाद से देश का सबसे बड़ा कर सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के लांच के साथ भारत ने विशेष स्थान प्राप्त किया है, लेकिन शुरू से ही इसका विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 1 जुलाई से भाजपा सरकार द्वारा पूरे देश में लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह वास्तविक जीएसटी नहीं है। उनका कहना है कि विशेषज्ञों द्वारा जीएसटी के लिए तैयार किया गया मसौदा कुछ और था। उनके अनुसार लागू किए गए इस जीएसटी से महंगाई दर प्रभावित होगी।

उन्होंने आगे कहा कि सूक्ष्म, लघु व मध्यम आय वाले व्यापारियों को इससे काफी नुकसान उठाना पड़ेगा।

जीएसटी पर संसद में भव्य समारोह गैरजरूरी - मुख्यमंत्री विजयन

तिरुवनंतपुरम

केरल के मुख्यमंत्री पीनाराई विजयन ने कहा है कि जीएसटी को लेकर संसद में मध्यरात्रि को हुआ भव्य समारोह का कोई मतलब नहीं बनता था। उन्होंने अपने एक फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि जबकि जीएसटी देश में कर सुधार की तरफ एक बड़ा कदम है, इसे लागू किये जाने पर ऐसा भव्य समारोह अनावश्यक था। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर लोगों के डर को दूर किया जाए तो बेहतर होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे फायदा आम नागरिकों को मिले, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जीएसटी को लंबी राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम बताया।

उन्होंने कहा कि हमें अभी भी जीएसटी को लेकर काफी लंबा जागरुकता अभियान चलाना है। लोगों को इसके बारे में बताना है व जीएसटी को लेकर उनके मन में उठ रहे सवालों का जवाब देना है। यह बदलाव छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगपतियों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दूसरी तरफ, कई विशेषज्ञों ने जीएसटी के सॉफ्टवेयर के प्रमाणिकता पर सवाल उठाए हैं।

विजयन ने यह भी कहा कि जीएसटी के लिए हर प्रकार के विचार-विमर्श के लिए केरल तैयार है, साथ ही केरल सरकार जीएसटी के कार्यान्वयन का स्वागत करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य हित की रक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है और राज्य को कर राजस्व में 20 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है।

इस बीच, राज्य के भाजपा अध्यक्ष कुम्मानम राजशेखरन ने कहा कि कांग्रेस और वामपंथी दलों ने जीएसटी लॉन्च समारोह से खुद को दूर रखकर अपने राजनीतिक अंधेपन का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी देश में आर्थिक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है तथा लांच समारोह से कांग्रेस और वाम दलों का बहिष्कार दुर्भाग्यपूर्ण है।

15 महीने की रणनीति का नतीजा थी पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक - पर्रिकर

नई दिल्ली

पूर्व रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में भारतीय जवानों द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान हमले से 15 महीने पहले ही बन चुका था। उन्होंने कहा कि 2015 में सेना ने म्यांमार की सीमा पर उग्रवादी विरोधी अभियान चलाया था।

उन्होंने कहा कि मणिपुर में भारतीय सेना के काफिले पर हुए हमले के बाद से ही पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति बनने लग गई थी। गोवा के मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, पीओके में आतंकवादियों पर किए गए लक्षित हमलों की योजना 15 महीने पहले बनी थी। चार जून, 2015 को पूर्वोत्तर के आतंकी समूह एनएससीएन-के ने मणिपुर के चंदेल जिले में भारतीय सेना के एक काफिले पर हमला कर 18 जवानों की जान ले ली थी। इसके बाद आठ जून को भारत ने भारत-म्यामांर की सीमा पर लक्षित हमले कर करीब 70-80 उग्रवादियों को मार गिराया। पर्रिकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सैन्यकर्मी राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ से एक टेलीविजन प्रस्तोता ने पूछा था, 'क्या आपमें देश के पश्चिमी मोर्चे पर भी ऐसा करने का साहस एवं क्षमता है। पूर्व रक्षामंत्री ने कहा कि उन्होंने तब ध्यान से सवाल सुना, लेकिन इसका जवाब सही समय पर देने का फैसला किया।

भारत को बड़े वैश्विक देशों में शुमार कराएगा जीएसटी - शाह

पणजी

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि वस्तु एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) की नयी कर प्रणाली से देश के आर्थिक विकास में इजाफा होगा। इससे इंस्पेक्टर राज भी खत्म होगा तथा भारत को बड़े वैश्विक देशों में शुमार होने में मदद मिलेगी।

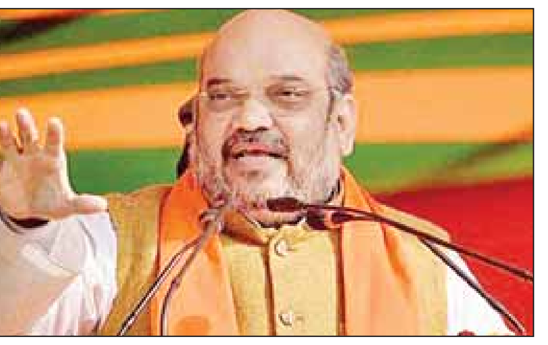

जीएसटी को पूरे देश में शुक्रवार को मध्यरात्रि में लागू किया गया है। दो दिन की यात्रा पर एक रैली में शामिल होने के लिए पणजी के पास डाबोलिम एयरपोर्ट पहुंच कर अमित शाह ने शनिवार को कहा कि जीएसटी लागू होने से 17 प्रकार के कर खत्म हो गए हैं। इन खत्म किए गए करों के स्थान पर पूरे देश में एक कर प्रणाली लागू कर दी गई है।

इससे कारोबारियों और छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी को लागू करने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन इनका भी समाधान हो जाएगा। लेकिन इस नयी कर प्रणाली से देश की अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार बढ़ेगी। इससे देश में वैश्विक नेतृत्व की क्षमता आएगी। इससे कुछ कर संबंधी कानूनों का भी खात्मा होगा।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीएसटी के लागू करने पर उन्होंने कहा कि मध्य रात्रि में भारत ने स्वतंत्रता दिवस से लेकर अब तक देश का सबसे बड़ा कर सुधार लागू किया है। हमने एक देश एक कर के सपने को साकार किया है। जब से मोदी सत्ता में आए हैं, वह हरेक क्षेत्र में नए चीजों को ला रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंचने पर शाह का पार्टी के 2500 कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर समेत उनके कई मंत्रियों और पार्टी नेताओं ने शाह की अगवानी की। इस यात्रा के दौरान अमित शाह ने गठबंधन के घटक दलों से भी बातचीत की। पणजी में पार्टी और घटक दलों के विधायकों से मुलाकात के अलावा उन्होंने उद्योगपतियों, होटल मालिकों, चाटर्ड एकाउंटेंटों और चिकित्सकों को भी संबोधित किया।

राष्ट्रपति चुनाव में मैं बलि का बकरा नहीं - मीरा कुमार

बेंगलुरु

विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार ने कहा है कि उन्हें देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए बलि का बकरा नहीं बनाया गया है।

राष्ट्रपति चुनाव में बलि का बकरा बनाए जाने के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मीरा कुमार ने शनिवार को कहा कि अपने आदर्शों और अपने अंदर की आवाज पर लड़ने वालों को बलि का बकरा नहीं कहा जा सकता। मैं एक योद्धा हूं और मैं लड़ूंगी। मुझे यकीन है कि इस लड़ाई में बहुत से लोग मेरा साथ देंगे। उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जाती हूं लोग पूछते हैं कि मेरे पास जीतने के लिए आंकड़े तो हैं ही नहीं। अगर आपके पास जीत के आंकड़े हैं तो आप कुल जोड़-घटाकर नतीजे घोषित क्यों नहीं कर देते। मैं जिन मूल्यों के लिए लड़ रही हूं, उन्हें किसी को तो आगे ले जाना होगा। तो क्या मैं अपना नाम वापस ले लूं? क्या मैं हार मान लूं? मीरा कुमार ने शनिवार को जनता दल एस के प्रमुख एचडी देवगौड़ा से मुलाकात की और उनसे अपने लिए समर्थन मांगा। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री और आरपीआइ के नेता रामदास आठवले ने विगत शुक्रवार को कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा था कि 17 जुलाई को होनेवाले राष्ट्रपति चुनाव में मीरा कुमार को विपक्ष का प्रत्याशी बनाकर उन्हें बलि का बकरा बना रही है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में कांग्रेस सांसदों और विधायकों से मुलाकात के बाद यह बात कही।

बांध के फाटकों के बंद कराने पर चुप क्यों हैं शिवराज सिंह चौहान- कांग्रेस

भोपाल

गुजरात सरकार द्वारा सरदार सरोवर बांध के गेट को बंद किए जाने मामले पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता अजय सिंह ने शनिवार को कहा इससे मध्यप्रदेश के 40 हजार लोग विस्थापित हो जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में बांध के गेट को बंद करने से भाजपा नीत मध्यप्रदेश की सरकार राजनीतिक फायदे के लिए जनता को दरकिनार कर रही है।

40 हजार लोग होंगे प्रभावित

सिंह ने कहा, सरदार सरोवर बांध के फाटकों के बंद होने से 192 गांवों में 40 हजार लोग प्रभावित होंगे। इनके पुर्नवास की कोई योजना नहीं है और गुजरात के फायदे के लिए सांसदों का हित देखा जा रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजनीतिक हित के कारण मामले पर चुप्पी साध रखी है। मध्यप्रदेश विधानसभा के विपक्षी नेता ने कहा, मैंने स्वयं प्रभावित गांवों का दौरा किया। इस दौरान मैंने देखा की एक बुजुर्ग महिला को पुर्नवास के नाम पर मात्र 1212 का कमरा आवंटित किया गया है। वह किसान है, वह अपने पालतू जानवरों और जरूरत के सामानों को कहां रखेगी।

गुजरात चुनाव है लक्ष्य

उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में अगले साल चुनाव होता है और वे किसी भी तरह भुज को पानी देना चाहते हैं और इसके लिए मध्यप्रदेश के विस्थापितों की पुर्नवास की चिंता किए बगैर बांध के फाटकों को बंद कर रहे हैं। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की नींव रखे जाने के 56 साल बाद विवादित बांध के फाटकों को केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद अंततः 17 जून को गुजरात सरकार ने बंद कर दिया।

किसानों की आत्महत्या जारी

राज्य में किसानों की आत्महत्या का हवाला देते हुए सिंह ने दावा किया कि पिछले 24 दिनों में करीब 53 किसानों ने खुदकुशी कर ली जो राज्य को मिले कृषि कर्मण अवार्ड पर बड़ा प्रश्नचिन्ह लगाता है। सिंह ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को किसानों के शोषण और दुखद स्थिति की व्याख्या के साथ पत्र लिख कर राज्य को मिलने वाले कृषि कर्मण सम्मान की जांच की मांग की है।

गिनीज बुक में नाम चाहती है सरकार

यह अवार्ड राज्य को देश में सर्वाधिक अनाज के उत्पादन के लिए दिया जाता रहा है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के क्रम में भाजपा नीत राज्य सरकार नर्मदा नदी के तट पर नमामि देवी नर्मदे कार्यक्रम के तहत 6 करोड़ पौधा लगाने का दावा कर बड़ी रकम खर्च कर रही है। सिंह ने कहा कि सरकार को राज्य में 2005-06 से 2016-17 के बीच लगाए गए 50.63 पौधों के लगाए जाने का रिकॉर्ड देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, किसानों को राहत देने के बजाए राज्य सरकार गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराने के लिए करोड़ों की राशि खर्च कर रही है।

शिवसेना ने पूछा सवाल, आज एयर इंडिया को बेचा जा रहा तो क्या कल कश्मीर भी नीलाम कर देगी सरकार

मुंबई

महाराष्ट्र और केंद्र में भाजपा की साथी शिवसेना भले ही सरकार का साथ दे रही हो, लेकिन कई मुद्दों पर भाजपा और शिवसेना की तनातनी देखी गई है। केंद्र और राज्य में साथ निभा रही शिवसेना ऐसी पार्टी बनकर सामने आई है जो सरकार के खिलाफ बोलने से भी नहीं हिचकिचाती है।

शिवसेना ने एक बार फिर सरकार पर तंज कसा है। इस बार एयर इंडिया के मुद्दे को लेकर पार्टी ने सरकार पर हमला किया है। सामना में लिखा गया है कि आज एयर इंडिया के कर्ज का बोझ नहीं झेला जा रहा है इसलिए उसे बेचा जा रहा है, कल अगर कश्मीर की सुरक्षा में हो रहा खर्च सहन नहीं हुआ तो क्या कश्मीर की भी नीलामी होगी?

इतना ही नहीं, सामना में आगे लिखा है कि अगर कांग्रेस सरकार के समय यह फैसला लिया गया होता तो, भाजपा उसके सारे कपड़े उतार देती और कहती सरकार एयर इंडिया नहीं चला सकती तो देश क्या चलाएगी, लेकिन ये काम भाजपा सरकार के दौरान हो रहा है और देश के गौरव एयर इंडिया को बेचा जा रहा है। 50 हजार करोड़ के घाटे में चल रही एयर इंडिया के बेचे जाने पर सामना में आगे लिखा गया है कि नौकरशाहों और एयर इंडिया के कर्मचारियों ने भारत की शान को बेच खाया है, जिसे भाजपा सरकार भी नहीं ठीक कर पा रही है। एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट ने एयर इंडिया में विनिवेश की मंजूरी दे दी है।